दैनिक जागरण
संवेदनाएं आत्मिक सुधार की सूत्रधार होती हैं

प्लास्टिक कचरे से मुक्ति

शायद ही कभी ऐसा हुआ हो जब प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में स्वच्छ भारत अभियान की चर्चा न की हो। इस बार भी उन्होंने इस अभियान को लेकर अपने मन की बात की, लेकिन इस दौरान उन्होंने आगामी 2 अक्टूबर से प्लास्टिक के खिलाफ अभियान शुरू करने का संदेश देकर एक ओर जहां पर्यावरण प्रेमियों के मन की मुराद पूरी की वहीं दूसरी ओर आम जनता का ध्यान एक गंभीर होती समस्या की ओर भी आकर्षित किया। ऐसा करना वक्त की जरूरत थी। चूंकि प्रधानमंत्री एक बार प्रयोग होने वाले प्लास्टिक के खिलाफ अभियान छेड़ने की जरूरत 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से भी जता चुके हैं इसलिए यह साफ है कि वह इस अभियान को जन आंदोलन का रूप देना चाहते हैं। किसी भी आंदोलन की सफलता जन भागीदारी पर निर्भर करती है। स्वच्छ भारत को नए आयाम देने वाला प्लास्टिक कचरे से मुक्ति का अभियान तभी सफल होगा जब आम लोग उसमें हर संभव तरीके से सहयोग देने के लिए आगे आएंगे। हर किसी को इससे परिचित होने की जरूरत है कि रोजमर्रा के जीवन में प्लास्टिक का आवश्यकता से अधिक इस्तेमाल पर्यावरण के लिए एक गंभीर समस्या बन गया है। प्लास्टिक का कचरा इसलिए पर्यावरण के लिए एक बड़ा संकट बन गया है, क्योंकि उसका क्षरण सैकड़ों वर्षों में होता है। यह संकट इतना गंभीर रूप लेता जा रहा है कि एक बार प्रयोग होने वाले प्लास्टिक का इस्तेमाल पूरी तरह बंद करने की नौबत आ सकती है। ऐसी कोई नौबत आए, इसके पहले ही हमें सचेत हो जाना चाहिए और इस क्रम में यह भी देखना चाहिए कि एक से अधिक बार इस्तेमाल होने वाली प्लास्टिक की ऐसी कौन सी वस्तुएं हैं जिनके प्रयोग से बचा जा सकता है, जैसे कि टूथब्रश।

निःसंदेह प्लास्टिक कचरे से पीछा तभी छूटेगा जब दैनिक उपयोग में आने वाली प्लास्टिक की वस्तुओं के विकल्प उपलब्ध कराए जाएंगे। यह अच्छी बात है कि कई सरकारी संस्थान एक बार प्रयोग में आने वाली प्लास्टिक की वस्तुओं का इस्तेमाल बंद करने जा रहे हैं। रेलवे एक बार प्रयुक्त होने वाली प्लास्टिक की चीजों का इस्तेमाल बंद करने जा रहा है तो लोकसभा सचिवालय ने संसद में प्लास्टिक की पानी की बोतलों के साथ प्लास्टिक की कुछ अन्य वस्तुओं के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस तरह के जो भी कदम उठाए जा रहे हैं उनका दायरा तेजी से फैलना चाहिए। इसी के साथ इस पर भी गौर किया जाना चाहिए कि प्लास्टिक के ऐसे कौन से उत्पाद हैं जिनके निर्माण पर यथाशीघ्र पाबंदी लगाई जा सकती है? बेहतर होगा कि प्लास्टिक की थैलियां बनाने पर रोक लगाई जाए।

जल संरक्षण की पहल

बिहार सरकार ने जलसंकट के निदान के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम पर जोर दिया है। यह एक अच्छी पहल है, बशर्ते इसका अनुपालन पूरी गंभीरता और सख्ती से किया जाए। भूगर्भीय जलस्तर में हो रही कमी के कारण पेयजल के साथ-साथ सिंचाई का भी संकट पैदा हो रहा है। गर्मी में तो हालत और बदतर हो जाती है, जब लोगों को पीने के पानी के लिए भी मशक्कत करनी पड़ती है। यह बहुत ही खतरनाक संकेत है। अगर इस पर गंभीर नहीं हुए तो आने वाले वर्षों में स्थिति और भी भयावह हो सकती है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की यह पहल सराहनीय है कि तालाब-पोखर जैसे जलस्रोतों को ढूंढकर निकाला जाए और इसे संरक्षित किया जाए। इसी कड़ी में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को सख्ती से लागू किए जाने के संबंध में नगर विकास एवं आवास विभाग का निर्देश भी अहम है। नियम तो बने हुए हैं, लेकिन हकीकत यही है कि यह सिर्फ कागज पर है। राज्य के अधिसंख्य हिस्सों में भवनों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम नहीं है। वर्षा का पानी बेकार चला जाता है और हम पानी के लिए तरसते रहते हैं। सरकार ने निर्देश जारी करते हुए कहा है कि सौ वर्गमीटर क्षेत्रफल वाले भवनों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम नहीं लगाने पर जुर्माने के साथ-साथ दंडात्मक कार्रवाई भी झेलनी पड़ेगी। वहीं जिन भवनों में यह सिस्टम है, उन्हें होल्डिंग टैक्स में पांच फीसद तक की छूट दी जाएगी। वर्षा जल संचयन का यह कारगर माध्यम है। इससे न सिर्फ भूगर्भीय जल संतुलन बना रहेगा, बल्कि पेयजल संकट की समस्या का भी निदान हो सकेगा। इस बात को समझना होगा कि जल का संरक्षण ही एक मात्र विकल्प है। जिस तेजी से आबादी बढ़ रही है, नए-नए रिहायशी इलाके बस रहे हैं, उस अनुपात में पानी की उपलब्धता भी होनी चाहिए। इसका एकमात्र उपाय बूंद-बूंद पानी का संचयन ही है। अधिकारियों का भी दायित्व बनता है कि सरकार के निर्देशों को पूरी गंभीरता से कार्यान्वित करने की पहल करें। इसके लिए अभियान चलाकर लोगों को जागरूक भी करना होगा। उन्हें समझाना होगा कि अगर अभी से सतर्क नहीं हुए तो आने वाले समय में घर-मकान तो होंगे, लेकिन पानी नहीं होगा। सरकार और प्रशासन के साथ आम जन की भागीदारी से यह मुहिम निश्चित रूप से सफल हो सकती है।

गलतियों की ओर संकेत करते कुछ स्वर

ए. सूर्यप्रकाश

पीएम मोदी की हमेशा आलोचना करने से कांग्रेस का भला नहीं होगा। कुछ कांग्रेसी इस गलती को स्वीकार करने लगे हैं। पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को भी इसे समझना होगा

आखिरकार कांग्रेस में कुछ समझदारी भरे स्वर सुनाई पड़ रहे हैं। वर्ष 2014 में लोकसभा में अपने निम्नतम आंकड़े पर सिमटने के बाद से ही कांग्रेस हकीकत से मुंह मोड़कर सिर्फ अपशब्दों की राजनीति में जुटी थी। मगर अब कांग्रेस के कुछ वरिष्ठ सदस्य अपने साथियों को वास्तविकता का सामना करने की सलाह दे रहे हैं। जयराम रमेश कांग्रेस के समझदार नेताओं में से एक माने जाते हैं। अक्सर अपनी राजनीतिक निष्ठा को सुनिश्चित रखने वाले रमेश ने कहा कि हर समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खलनायक की तरह पेश करने से कांग्रेस का कोई भला नहीं होने वाला, क्योंकि उनका शासन पूरी तरह नकारात्मक नहीं है। वह प्रधानमंत्री के सुशासन के एजेंडे और उज्ज्वला जैसी योजनाओं से खासे प्रभावित दिखे जिससे गरीब महिलाओं को रसोई गैस मिली और प्रधानमंत्री राजनीतिक रूप से ताकतवर हुए। कांग्रेस के एक और वरिष्ठ नेता अभिषेक सिंघवी ने भी रमेश के सुर में सुर मिलाते हुए कहा कि मोदी को खलनायक की तरह पेश करना गलत था। मोदी सरकार के फैसलों की समीक्षा व्यक्ति नहीं, बल्कि मुद्दों पर आधारित होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि उज्ज्वला उनके अच्छे कार्यों में से एक है।

इन दोनों नेताओं के ये बयान सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जैसे पार्टी के शीर्ष नेताओं के रुख-रवैये से उलट हैं जो हर मुद्दे पर लगातार प्रधानमंत्री मोदी की आलोचना में जुटे हैं। वास्तव में मोदी सरकार ने कई ऐसे अहम फैसले लिए हैं जिनकी देश भर में चहुंओर वाहवाही हुई, लेकिन नेहरू-गांधी परिवार की ओर से मोदी की तारीफ में एक बोल नहीं फूटा। मोदी-शाह की जोड़ी द्वारा कश्मीर में अनुच्छेद 370 समाप्त करने के फैसले के बाद पार्टी नेताओं में अफरातफरी का माहौल है। पार्टी दिग्गजों में भारी दुविधा की जड़ें कांग्रेस की उस प्रतिबद्धता में हैं कि वह किसी भी कीमत पर अनुच्छेद 370 को कायम रखेगी। इस साल अप्रैल में ही लोकसभा चुनावों के लिए अपने घोषणापत्र में उसने एलान किया था कि किसी भी सूरत में 'संवैधानिक स्थिति' में बदलाव नहीं किया जाएगा। इस मसले पर स्वयं को ऐसे उलझाकर कांग्रेस अपने उसी पुराने रुख पर टिकी है जो मुद्दा भारत की एकता एवं अखंडता के लिए हमेशा से एक अवरोध रहा है। इसीलिए राहुल गांधी ने एलान किया कि एकतरफा जबरिया कदमों से राष्ट्रीय एकीकरण नहीं किया जा सकता। वहीं प्रियंका गांधी ने ट्वीट करके पूछा कि 'क्या मोदी-शाह की सरकार मानती है कि भारत अभी भी एक लोकतंत्र है?'

अफसोस की बात है कि ऐसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मुद्दों पर कांग्रेस अपना दिमाग लगाती नहीं दिख रही। उन्नीस सौ साठ के दशक के उत्तरार्ध में जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को अपनी सरकार चलाने के लिए वामपंथियों की बैसाखी का मोहताज होना पड़ा तबसे पार्टी पर वामपंथी नेताओं और बुद्धिजीवियों की सोच हावी होती गई। इसका नतीजा यही निकला कि कांग्रेस ने अपनी राष्ट्रवादी विचारधारा का चोला पूरी तरह उतार फेंका। मौजूदा दौर में भाजपा राष्ट्रवाद के खांचे में पूरी तरह फिट हो गई है और कांग्रेस को सूझ नहीं रहा कि वह आगे कौन सा कदम उठाए। परिणामस्वरूप, आप देखेंगे कि तमाम अहम मुद्दों पर कांग्रेस और कम्युनिस्टों के सुर एक जैसे सुनाई पड़ेंगे। राहुल गांधी के बाद पी चिदंबरम ने सरकार पर राज्य के साथ पक्षपात का आरोप लगाया। यह रुख सीताराम येचुरी जैसे तमाम वामपंथी नेताओं के जैसा ही था जो मांग कर रहे थे कि जम्मू-कश्मीर का पुराना दर्जा बहाल किया जाए।

हालांकि अनुच्छेद 370 को लेकर पार्टी की प्रतिक्रिया को अलग करके नहीं देखा जाए। यह उसी शंकालु और अविश्वास भरे रवैये के अनुरूप है जिसमें पार्टी ने सुरक्षा बलों द्वारा सर्जिकल स्ट्राइक जैसी कार्रवाई को भी संदेह की दृष्टि से देखा। जहां पूरा देश सीमा पार आतंकी ठिकानों को निशाना बनाने वाले हमारे सैनिकों के शौर्य और प्रतिबद्धता की प्रशंसा में जुटा था वहीं कांग्रेस यह दावा कर रही थी कि उसके शासनकाल में भी ऐसी कई सर्जिकल स्ट्राइक की गई थीं। हालांकि उसके इस दावे को ज्यादा भाव नहीं दिया गया। जब महाराष्ट्र के एक कांग्रेसी नेता ने सर्जिकल स्ट्राइक को फर्जी बताया तो चिदंबरम ने उसके सुबूत मांग लिए। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री पर आरोप लगाए कि वह सर्जिकल स्ट्राइक से सियासी फायदा बना रहे हैं। मानों इतना ही काफी नहीं था। इस साल 26 फरवरी को बालाकोट में आतंकी संगठन जैश-ए-मुहम्मद के ठिकानों पर भारतीय वायुसेना की साहसिक स्ट्राइक के बाद भी उनके इस रवैये में बदलाव नहीं आया। चिदंबरम ने इस पर सवाल उठाया कि वायुसेना के इस हमले में कितने आतंकी मारे गए। एक अन्य कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू तो एयर स्ट्राइक की मंशा पर ही सवाल खड़े करने लगे। इसे चुनावी तिकड़म तक बताया गया।

अब सामाजिक कल्याण की दिशा में मोदी सरकार की कुछ अहम योजनाओं की अभूतपूर्व सफलता पर भी गौर किया जाए। इनमें उज्ज्वला योजना बाजी पलटने वाली साबित हुई है जिसके तहत छह करोड़ परिवारों को रसोई गैस मुहैया कराई गई है। अगले एकाध साल में दो करोड़ परिवारों को भी इसका लाभ उपलब्ध कराने की तैयारी हो रही है। गरीब परिवारों को सालाना पांच लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा आवरण भी दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है। ऐसे ही गरीबों के लिए जन-धन खाते की योजना को शानदार सफलता मिली जिसके तहत 36 करोड़ नए बैंक खाते खुले। यह भी एक विश्व कीर्तिमान है। ऐसी तमाम योजनाएं हैं जिनकी मोदी सरकार ने संकल्पना पेश कर उन्हें अमली जामा पहनाया, लेकिन नेहरू गांधी परिवार ने कभी इनमें से किसी योजना के प्रभाव को स्वीकार करना गवारा नहीं समझा। उनसे संकेत लेते हुए कांग्रेस के तमाम नेताओं ने इन योजनाओं में मीनमेख निकालने में ही अपना ज्यादा वक्त जाया किया। यह उन तमाम लोगों को जरा भी रास नहीं आया जिन्हें इन योजनाओं से फायदा पहुंचा था।

सरदार पटेल और डॉ. बीआर आंबेडकर के दिनों से ही अन्य राष्ट्रीय नायकों की उपलब्धियों के प्रति नेहरू-गांधी परिवार की असहिष्णुता अब एक स्थापित सत्य बन चुकी है और हाल के वर्षों में इसकी पर्याप्त रूप से पुष्टि हुई है। कई दशकों तक परिवार इस खेल को खेलकर बच निकलता रहा, लेकिन अब लोग उनकी इस संकीर्णता और ईर्ष्या भाव को समझने लगे हैं। इससे भी बढ़कर यह बात रही कि जनजागरूकता ने इस परिवार के लिए चुनावी सफलता का रास्ता सिकोड़ दिया है। अगर कांग्रेस अपना सियासी नुकसान कम करना चाहती है तो सरकारी घोषणाओं एवं योजनाओं पर उसे अपनी प्रतिक्रिया और विश्वसनीय बनानी होगी। जयराम रमेश ने इसका रास्ता दिखाया है। उम्मीद है कि अन्य नेता भी उनका अनुसरण करेंगे।

(लेखक प्रसार भारती के चेयरमैन एवं वरिष्ठ स्तंभकार हैं)

response@jagran.com

शिक्षा क्षेत्र में परिवर्तन की सही राह

जगमोहन सिंह राजपूत

नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति जरूरी है, मगर उससे भी अहम है उन लोगों का प्रशिक्षण जिन पर इसे लागू करने का जिम्मा है

किसी भी राष्ट्र की प्रगति, परिवर्तन और प्रसन्नता का स्तर वहां के नागरिकों के मध्य समझ, सहयोग, पारस्परिक सम्मान, नवाचार में रुचि तथा मानवीय मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता के परिमाण पर निर्भर करता है। इसके लिए जरूरी है कि प्रत्येक बच्चे के संपूर्ण व्यक्तित्व विकास का उत्तरदायित्व राष्ट्र तथा समाज स्वीकार कर ईमानदारी से इसका क्रियान्वयन करे। साथ ही प्रत्येक बच्चे को ज्ञान, कौशल, मानवीय संवेदनाओं और मूल्यों को सीखने तथा जीवन में उतारने के लिए आवश्यक वातावरण, सहयोग, मार्गदर्शन तथा उत्साहवर्धन मिले। अर्थात हर एक बच्चे को प्रशिक्षित, प्रतिबद्ध तथा उत्साही अध्यापक मिलें और उनसे बच्चों को रुचिकर ढंग से सही विद्या और अच्छी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले। नई शिक्षा नीति प्रारूप-2019 यानी कस्तूरीरंगन समिति के प्रतिवेदन में शिक्षकों संबंधी अध्याय में यह सुनिश्चित करना उद्देश्य के रूप में प्रस्तुत किया गया है कि स्कूल शिक्षा के सभी स्तरों पर सभी विद्यार्थियों का शिक्षण 'उत्साहित, प्रेरित, उच्च योग्यता प्राप्त, पेशेवर रूप से प्रशिक्षित शिक्षकों' द्वारा ही हो।

नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लाना आवश्यक है, मगर उससे भी महत्वपूर्ण है उन लोगों का 'उत्साहित, प्रेरित और प्रशिक्षित' होना जिन्हें उसके क्रियान्वयन की जिम्मेदारी सौंपी जानी है। अध्यापकों के संबंध में मानवीय स्तर पर हर सभ्यता में और हर भाषा में जो सर्वोत्तम कहा जा सकता है, कहा जा चुका है। भारत में गुरु को ईश्वर के भी पहले स्थान देने की परंपरा रही है। प्रश्न यह है कि व्यवहार में आज स्थिति क्या है? यह तो सर्वत्र माना ही जाता है कि किसी भी देश के लोगों का स्तर वहां के अध्यापकों के स्तर से ऊंचा नहीं हो सकता है। यह वाक्य अपने आप में बहुत कुछ कहता है, 'किसी भी देश की प्रगति और विकास की गति और गुणवत्ता वहां के अध्यापकों की कार्य-कुशलता और प्रतिबद्धता तथा उनके द्वारा अपने जीवन में उतारे गए मूल्यों से ही निर्धारित होती है।' गुरु, अध्यापक या आचार्य से एक अपेक्षा तो समाज तथा हर व्यक्ति को होती है कि उनका अपना आचरण अनुकरणीय हो, क्योंकि वे राष्ट्र की भावी पीढ़ी का निर्माण करते हैं, वे ही राष्ट्र निर्माण की संरचना को मजबूती देते हैं, वे ही राष्ट्र निर्माण के आधार स्तंभ हैं।

इस समय भारत के शिक्षक वैश्विक परिदृश्य में कहां हैं? 2012 में जस्टिस जेएस वर्मा आयोग ने अपने प्रतिवेदन में कहा था कि देश में 17,000 से अधिक शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान हैं जिनमें 92 प्रतिशत निजी प्रबंधन के अंतर्गत आते हैं। इनमें से अधिकांश अच्छा प्रशिक्षण देने का प्रयास ही नहीं करते हैं! यहां यह याद करना समीचीन होगा कि पत्राचार द्वारा सरकारी तथा गैर सरकारी विश्वविद्यालयों द्वारा की जा रही शिक्षक प्रशिक्षण की उपाधियों की गिरती गुणवत्ता से चिंतित वरिष्ठ शिक्षाविदों के लगभग बीस वर्ष के अथक प्रयास के पश्चात राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् अधिनियम 1993 संसद में स्वीकृत हुआ। 1998-99 में यह संस्था पूरी तरह क्रियाशील हो गई तथा इसने कम गुणवत्ता वाले अनेक पाठ्यक्रमों को नियमित करने में सफलता पाई। बाद में यह अपने उस स्वरूप को कायम नहीं रख सकी तथा प्रवाह के साथ ही बहने लगी। परिणाम सामने है।

नई शिक्षा नीति ने व्यवस्था के समक्ष यह बड़ी चुनौती प्रस्तुत की है। क्या इसका समाधान संभव है? नियुक्ति की प्रक्रिया बदलकर, प्रशिक्षण का पाठ्यक्रम बदल कर और सेवा शर्तों को अधिक स्वीकार्य बनाकर किए गए परिवर्तन आशा तो जनित कर सकते हैं, मगर सही क्रियान्वयन का आश्वासन नहीं बन सकते हैं। यदि सही क्रियान्वयन हो तो नई नीति हर बच्चे को शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और आत्मिक विकास के मार्ग पर आगे बढ़ा सकेगी। ये चार तत्व भारत की परंपरागत शिक्षा व्यवस्था की धुरी रहे हैं। नई नीतियां भी इन्हीं चार मुख्य बिंदुओं के इर्द-गिर्द ही बननी होंगी। जो देश यह नहीं समझ सकेगा वह पीछे रह जाएगा। यह भी निर्विवाद है कि सार्थक और सफल परिवर्तन में सबसे महत्वपूर्ण योगदान अध्यापक का होगा। इस समय विश्व में सर्वाधिक प्रतिष्ठा फिनलैंड की शिक्षा व्यवस्था की है। हर कोई फिनलैंड के समकक्ष शैक्षिक उपलब्धियां प्राप्त करना चाहता है, लेकिन फिनलैंड शीर्ष स्थान पर पहुंचा कैसे इस पर चर्चा करने में भी नीति निर्धारक सहज नहीं रह पाते हैं।

दरअसल फिनलैंड की शिक्षा व्यवस्था में बड़ा सुधार शिक्षा की संकल्पना में बदलाव का था। उसने यह माना कि सार्थक परिवर्तन की कुंजी शिक्षक प्रशिक्षण में ही निहित है। 1974 में फिनलैंड ने इस प्रशिक्षण का सारा दायित्व अपने विश्वविद्यालयों में स्थानांतरित कर दिया। 1979 में उसने स्नातकोत्तर उपाधि अनिवार्य कर दी। 2019 में भारत में कस्तूरीरंगन समिति ने ऐसी ही सिफारिशें की हैं। फिनलैंड में प्रतिभावान तथा अध्ययन और अध्यापन में रुचि रखने वाले ही इस व्यवसाय में प्रवेश करते हैं। अध्यापक किसी से कम वेतन नहीं पाते हैं। वहां के नेशनल बोर्ड ऑफ एजुकेशन ने मूल पाठ्यक्रम की रूपरेखा 1994 में बनाकर स्कूलों और निकायों को सौंप दी। इसका विशद स्वरूप स्थानीय स्तर पर निर्धारित होता है। यह अध्यापकों पर गहन विश्वास का द्योतक था और उन्होंने अपना उत्तरदायित्व न केवल समझा, बल्कि उसका 'प्रेरित और उत्साहित' होकर अनुपालन भी किया।

आज सारा विश्व फिनलैंड के 'अपने अध्यापकों पर विश्वास' कर शैक्षिक श्रेष्ठता प्राप्त करने की वास्तविकता को आश्चर्य से देख रहा है। वैसे इस प्रकार के नवाचार की नकल कर पाना भी आसान नहीं है। ऐसे परिवर्तन तभी संभव होते हैं जब सरकार, समाज और परिवार सभी एक-दूसरे पर विश्वास करते हुए इसकी सफलता में जुट जाएं। यदि देश में दशकों तक दस-बारह लाख अध्यापकों के पद रिक्त रहें, लगभग उतने ही अनियमित थोड़े से मानदेय पर गैर-पेशेवर शिक्षक नियुक्त किए जाएं तो फिनलैंड जाकर केवल पर्यटन का आनंद ही लिया जा सकेगा और कुछ नहीं मिलेगा। फिनलैंड में अध्यापकों को निरीक्षकों (जिला शिक्षा अधिकारियों) की चिंता नहीं करनी पड़ती है। उन्हें जिला अधिकारी अन्य गैर शैक्षिक कार्यों में नहीं लगाता है। वहां के अध्यापक साल भर में 600 घंटे अध्यापन करते हैं, जबकि ब्रिटेन में यह 900 घंटे तथा अमेरिका में 1100 घंटे है। क्या हम इसके लिए तैयार हैं?

(लेखक एनसीईआरटी के पूर्व निदेशक हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

संतुष्टता

संतुष्टता सबसे बड़ा खजाना और शक्ति भी है। मनुष्य आत्मा के मूलभूत सात गुण हैं। जैसे कि शांति, प्रेम, पवित्रता, सुख, आनंद, आत्मज्ञान और आत्मशक्ति। जब किसी इंसान में ये सारे गुण पूर्णता में मौजूद होते हैं तो वह इंसान सतोगुणी कहलाता है और इन गुणों का समावेश ही संतुष्टता है। संतोष रूपी धन के सामने दुनिया की धन दौलत भी फीकी पड़ जाती है। ऐसा इसलिए, क्योंकि संसार के सारे वैभव और भौतिक सुख-सुविधाएं भी मनुष्य को सच्ची संतुष्टि देने में असमर्थ होते हैं। यह सच है, मनुष्य की सांसारिक इच्छाओं की कोई सीमा नहीं होती है। महात्मा बुद्ध के अनुसार भौतिक इच्छाएं या कामनाएं ही इंसान के दुखों का कारण हैं। भौतिक कामनाओं का अंत ही दुख का अंत है। इसलिए उन्होंने कामनाओं को शुभ कामनाओं में बदलने का मार्ग दिखाया। शास्त्रों में 'इच्छा मात्रम अविद्या' कहा गया है। और यह भी कहा यह है कि 'सा विद्या या विमुक्तये' अर्थात वही विद्या है, जो मनुष्य को कामनाओं और इंद्रिय भोग से जन्मे रोग, कष्ट और दुख से मुक्ति दिलाए।

संतुष्टता मानव को निष्क्रिय नहीं, अपितु क्रियाशील, सृजनशील, सकारात्मक, आशावादी, निष्ठावान, ईमानदार और प्रगतिशील बनाती है। सच्चाई, अच्छाई और सबकी भलाई के लिए उमंग, उत्साह, साहस, आत्मविश्वास और मनोबल के साथ आगे बढ़ने के लिए लोगों को प्रेरित करती है।

संतुष्ट व्यक्ति शांत, शीतल, संतुलित, सहनशील, धैर्यवान, लचीला और मिलनसार होता है। श्रीमदभगवद्गीता के अर्जुन के समान सभी मानसिक द्वंद्वों और प्रश्नों से परे प्रसन्न रहता है। कार्यक्षेत्र में कर्मयोगी बन समाधानात्मक बुद्धि से हर कार्य में सफल, संतुष्ट और स्थितप्रज्ञ रहता है। संतुष्टता को बढ़ाने के लिए अंतरात्मा में निहित सातों गुणों के बारे में नियमित मनन, चिंतन एवं अनुभूति जरूरी है। इन गुण और शक्तियों को परमात्मा से, मन-बुद्धि से जोड़े रहने की आवश्यकता होती है।

ब्रह्मा कुमारी सुनिता

संसाधनों के अपव्यय का खतरा

सुधीर कुमार

2019 में धरती द्वारा उत्पादित जिस संसाधन को हमें 365 दिन उपभोग करना था, उसे हमने 209वें दिन ही खत्म कर दिया

'अर्थ ओवर शूट डे' सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम ब्रिटेन की न्यू इकोनॉमिक संस्था के एंड्रयू सिम्स ने किया था। धरती एक साल में जितने संसाधन उत्पादित करती है, दुनियाभर की आबादी उन संसाधनों का साल पूरा होने से पहले जिस दिन तक उपभोग कर लेती है, उस तिथि को 'अर्थ ओवरशूट डे' के नाम से जाना जाता है। ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क के मुताबिक 2019 में यह तिथि 29 जुलाई को चिन्हित किया गया। इसका अभिप्राय यह हुआ कि 2019 में धरती द्वारा उत्पादित जिस संसाधन को हमें 365 दिन उपभोग करना था, उसे हमने 29 जुलाई यानी साल के 209वें दिन ही खत्म कर दिया। इसका अर्थ यह भी हुआ कि साल के बाकी 156 दिन हम संसाधन के जिस हिस्से का उपभोग करेंगे, वह आने वाली पीढ़ी से लिया गया उधार होगा!

दरअसल जिस गति से विश्व में जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, उस अनुपात में प्राकृतिक संसाधनों का दोहन भी तेजी से बढ़ रहा है, जिससे 'अर्थ ओवरशूट डे' की अवधि भी सिमटती जा रही है। 1969 में साल भर का संसाधन 13 महीने में खपत होता था, लेकिन आज वह वर्ष के सातवें या आठवें महीने में ही खत्म हो जा रहा है! 2018 में यह तिथि एक अगस्त को आया था। यह साबित करता है कि मानव समुदाय द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का बड़ी तेजी से और अंधाधुंध दोहन किया जा रहा है।

औद्योगिक विकास के नाम पर पृथ्वी पर आज जिस प्रकार प्राकृतिक संसाधनों का अपव्यय किया जा रहा है, उसके कारण न केवल इन संसाधनों के स्रोत समाप्त हो रहे हैं, बल्कि प्रदूषण में वृद्धि, प्रदूषण-जनित बीमारियों का प्रसार, सूखा पड़ने, मरुस्थलों का विस्तार तथा प्राकृतिक असंतुलन जैसी विभिन्न समस्याएं भी बढ़ी हैं। हालांकि पृथ्वी के पास उतनी क्षमता है कि समस्त जनसंख्या के आवश्यकताओं की पूर्ति वह कर सकती है, लेकिन स्वार्थ और लालच की वजह से प्राकृतिक संसाधन सिकुड़ते जा रहे हैं। विशेषकर वनों की कटाई, मृदा क्षरण, जैव विविधता के ह्रास और वातावरण में घुलती कॉर्बन डाईऑक्साइड जैसे कारक पारिस्थितिक असंतुलन के लिए जिम्मेवार रहे हैं।

बहरहाल संसाधनों के बेतहाशा दोहन को रोकने के लिए एक ओर जहां विकास के सततपोषणीय स्वरूप पर जोर देने की आवश्यकता है, वहीं नागरिकों से भी उम्मीद की जाती है कि वे प्राकृतिक संसाधनों का विवेकपूर्ण तरीके से इस्तेमाल करें। अनवीकरणीय संसाधन (कोयला, गैस, पेट्रोलियम), जिसकी मात्रा सीमित है, उसका कम से कम इस्तेमाल करने तथा नवीकरणीय संसाधनों जैसे सौर, पवन और भूतापीय ऊर्जा के इस्तेमाल पर जोर देने से हालात सुधर सकते हैं। इसके अलावा वनीकरण को बढ़ावा देकर, ऊर्जा संसाधनों की बर्बादी रोककर और जागरूकता का प्रसार करके भी संसाधनों का अपव्यय रोका जा सकता है। स्मरण रहे, प्रकृति के साथ तालमेल बैठा कर चलने से ही सुखी जीवन बिताया जा सकता है।

(लेखक बीएचयू में अध्येता हैं)

मेलबाक्स

एक बहुआयामी व्यक्तित्व का अवसान

सरल हृदय वाले विराट राजनेता शीर्षक से युक्त अपने आलेख में भूपेंद्र यादव ने अरुण जेटली के व्यक्तित्व को जिस विराटता से निरूपित किया है, वह उनकी महत्ता को रेखांकित कर रहा है। बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी जेटली का यूं चले जाना हृदयघाती बन गया। अल्पसमय में ही यह देश एक और विराट व्यक्तित्व के दुखद अवसान का साक्षी बना। अभी कुछ दिनों पहले इसी अगस्त माह में इस देश ने एक विदुषी राजनेत्री सुषमा स्वराज को खोया था और अब अरुण जेटली जैसे प्रखर राजनेता और विधिवेत्ता भी चले गए। इन द्वय राजनेताओं का असामयिक निधन भारतीय राजनीति की अपूर्णनीय क्षति है। दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रनेता के रूप में अपना राजनीतिक सफर शुरू करने वाले जेटली ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। आपातकाल के प्रताड़नापूर्ण दौर से गुजरते हुए वो अटल-आडवाणी के नेतृत्व में गठित होने वाली भाजपा के सच्चे सिपाही बने। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में विधि मंत्री रहते हुए उन्होंने एक श्रेष्ठ विधिवेत्ता के रूप में अपने दायित्व का निर्वाह किया। 2014 में पूर्ण बहुमत वाली मोदी सरकार में उनको वित्त मंत्री का गुरुतर दायित्व सौंपा गया। केंद्रीय वित्त मंत्री के रूप में आपने बहुप्रतीक्षित जीएसटी के क्रियान्वयन में आने वाली तमाम रुकावटों को दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अपनी तर्क शक्ति से विपक्षी नेताओं को सहमति के कगार पर खड़ा करने में उन्हें महारत हासिल थी। एक धीर-गंभीर राजनेता के रूप में विपक्षी दल के लोग भी उनका सम्मान करते थे। विदेश यात्रा पर गए प्रधानमंत्री मोदी ने अपने परम सहयोगी और मित्र अरुण जेटली के आकस्मिक निधन से भाव-विह्वल होकर जो शोक व्यक्त किया, वह संवेदनशील था। जेटली ने अपने राजनीतिक जीवन में राजनीतिक शुचिता के जो मानदंड स्थापित किए, वो अनुकरणीय हैं। प्रखर राजनेता के साथ एक अध्ययनशील बुद्धिजीवी एवं तार्किक वकील के रूप में उनके द्वारा अर्जित राष्ट्रव्यापी ख्याति ने उनके व्यक्तित्व को वास्तव में विराट बना दिया।

डॉ. वीपी पाण्डेय, अलीगढ़

विरोध की राजनीति

राजनीति में विपक्ष की भी बड़ी जिम्मेदारी होती है। सरकार को गलत काम से रोकने के लिए विरोध और अच्छे काम पर समर्थन करना उसका दायित्व है। मगर वर्तमान में विपक्ष अपनी जिम्मेदारी को निभाने में विफल साबित हो रहा है। सत्तापक्ष की हर बात का विरोध करने का परिणाम यह होता है कि जनता उसकी बात पर ध्यान देना छोड़ देती है। कांग्रेस हाईकमान को यह बात समझ नहीं आ रही, किंतु उनके नेताओं जयराम रमेश, शशि थरूर और अभिषेक मनु सिंघवी अवश्य ही समझ रहे हैं। पिछले पांच से अधिक वर्ष से, जबसे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं अथवा राजग की सरकार बनी है, कांग्रेस के शीर्ष नेताओं ने उनके हर सही-गलत कार्य का एकतरफा विरोध किया है। किसी अच्छे कार्य की प्रशंसा एक बार भी नहीं की। नोटबंदी, सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक और तीन तलाक का तो जोरदार विरोध किया ही, साथ में राष्ट्रहित से जुड़े अतिसंवेदनशील मुद्दे अनुच्छेद 370 का भी जबरदस्त विरोध कर बैठे। होना यह चाहिए था कि राष्ट्रीय एकता से जुड़े इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर सरकार का साथ देते, लेकिन यहां भी कांग्रेस ने इसे अपनी नाक का सवाल समझा। कांग्रेस का यह विरोध पाकिस्तान का हौसला बढ़ाने का काम करेगा। कांग्रेस को चाहिए कि वह अपनी आंखों से सरकार के विरोध की मोटी परत को हटाकर राष्ट्रहित के लिए सरकार के सही कार्यों की प्रशंसा करे। इससे कांग्रेस की छवि और जनाधार में वृद्धि ही होगी।

सतप्रकाश सनोठिया, रोहिणी

कैमरों में कैद जिंदगी

हर युवा आज स्मार्टफोन के जरिये खुद की जिंदगी को कैमरों में कैद करने में जुटा है, कहीं वीडियो तो कहीं तस्वीरों के रूप में। आज का युवा अपने समय का एक बड़ा हिस्सा इन डिजिटल कैमरों के सामने गुजार रहा है। यहां ध्यान देने वाली बात ये है कि हर कोई अपनी जिंदगी का बस वही हिस्सा साझा करना चाहता है जिसमें वो खुश है और इस तरह से हर कोई अपनी परेशानियों को खुद में ही समे